गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

अहमदाबाद से प्रकाशित होता दैनिक

संपादक : श्री मनोजकुमार चंपकलाल शाह

रजी.ओफिस : टी.एफ-०१,नानकराम सुपर मार्केट,रामनगर,साबरमती,अहमदाबाद- ३८० ००५.गुजरात,भारत.

फोन /फेक्स : (०७९) २७५७ ३३०७, ९०१६३ ३३३०७ (मो) ९३२८३ ३३३०७, ९८२५३ ३३३०७, Email : • Email : garvigujarat2007@gmail.comgarvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

वर्ष : 08 | अंक : 311 | दि. 12-03-2019 मंगलवार | वि.सं. 2075 | फागण सुद -०६ | पाना : 04 | किंमत : 00.50 पैसा

जानकारी मिलने के बाद त्राल में बड़ा ऑपरेशन किया गया

पुलवामा में हमले के मास्टरमाइंड मुदस्सिर खान को ढेर कर दिया गया

पुलवामा जिले के त्राल में एनकाउंटर में तीन आतंकवादी मार गिराए गए भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए : सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी

(संपूर्ण समाचार सेवा) श्रीनगर,

१४ फरवरी को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड मुदस्सिर अहम खान को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया है। सुरक्षाबलों के लिए इसे बड़ी कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सोमवार को हुए एक एनकाउंटर में तीन आतंकी मार गिराए गए। मारे गए आतंकियों में जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर मुदस्सिर अहमद खान उर्फ मोहम्मद भाई भी शामिल है। जैश के कमांडर मुदस्सिर खान के परिवार ने उसके शव की शिनाख्त त्राल एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों में से एक के रूप में की है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। अभी फरेंसिक रिपोर्ट के आने का इंतजार किया जा रहा है। एक अधिकारी ने कहा कि मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान जेआईएम कमांडर मुदासिर खान उर्फ मोहम्मद भाई के रूप में की गई है। उन्होंने बताया कि शवों के डीएनए परीक्षण किए जाएंगे। जिस घर में आतंकवादी छिपे हुए थे, सुरक्षाबलों के अभियान में वह घर पूरी तरह से नष्ट हो गया। सेना ने कहा है कि तीन आतंकवादी मारे गए हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी तक सिर्फ दो शव बरामद किए हैं। सोमवार रात त्राल के पिंगलिश इलाके में एनकाउंटर के दौरान जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी मार गिराए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि मुदस्सिर उन तीन आतंकियों में से एक है जो मुठभेड़ में ढेर किए गए हैं। एनकाउंटर में मारे गए तीनों आतंकियों के शव बुरी तरह से जल गए हैं और उनकी शिनाख्त की कोशिश की जा रही है। सुरक्षाबलों ने आतंकियों की मौजूदगी का खुफिया इनपुट मिलने के बाद पिंगलिश इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। सर्च पार्टी पर जब घात लगाकर बैठे आतंकियों ने फायरिंग की तो यह अभियान एक एनकाउंटर में तब्दील हो गया। इसके बाद सुरक्षाबलों ने जवाबी फायरिंग करते हुए आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों में कम चर्चित मुदस्सिर को पुलवामा टेरर अटैक का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इस हमले में सीआरपीएफ के ४० जवान शहीद हो गए थे। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पुलवामा के ही निवासी २३ साल का मुदस्सिर एक इलेक्ट्रिशन था और उसके पास ग्रैजुएट की डिग्री थी। अधिकारियों के मुताबिक आतंकी हमले में इस्तेमाल की गई गाड़ी और विस्फोटक का इंतजाम उसी ने किया था। त्राल के मीर मोहल्ले के रहने वाले मुदस्सिर ने २०१७ में एक ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद जॉइन किया था। बाद में उसे नूर मोहम्मद तांत्रे उर्फ नूर त्राली ने जैश में सक्रिय रूप से जिम्मेदारी सौंपी। नूर पर कश्मीर घाटी में आतंकी संगठनों को दोबारा उठ खड़े होने में मदद पहुंचाने का आरोप है। जनवरी २०१८ में लेथपोरा में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले में भी उसका नाम आया। इस हमले में पांच सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले की जांच कर रही एनआईए ने २७ फरवरी को मुदस्सिर के घर पर छापा मारा था। पुलवामा में इस्तेमाल की गई मारुति इको मिनीवैन को जैश के ही एक संदिग्ध ने हमले से १० दिन पहले खरीदा था। संदिग्ध की पहचान साउथ कश्मीर के बिजबेहारा के रहने वाले सज्जाद बट के रूप में हुई थी।

पुलवामा हमले में प्रत्यक्ष रूप से शामिल था

मुदस्सिर अहेमद आत्मघाती बॉम्बर के सीधा संपर्क में था

(संपूर्ण समाचार सेवा) श्रीनगर,

दिसंबर २०१७ में तांत्रे के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद मुदस्सिर अपने घर से १४ जनवरी २०१८ को फरार हो गया था। उसके बाद से ही वह जैश की साजिश में सक्रिय भूमिका निभा रहा था। अधिकारियों का कहना है कि वह आत्मघाती आतंकी आदिल अहमद डार के लगातार संपर्क में था। आदिल ने ही सीआरपीएफ के काफिले में चल रही बस में विस्फोटकों से लदी कार से टक्कर मारी थी। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुदस्सिर खान ने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (ITI) से इलेक्ट्रिशन का एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया था। बताया जा रहा है कि एक मजदूर पिता का बेटा मुदस्सिर फरवरी २०१८ में सुंजवां में हुए आतंकी हमले में भी शामिल था। इस अटैक में सुरक्षाबलों के छह जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा एक नागरिक की भी मौत हो गई थी।

पुलवामा हमले में गाड़ी, हथियार की व्यवस्था की थी

रमजान के दौरान लोकसभा चुनाव के लिए मतदान

मुस्लिम मौलानाओं और नेताओं ने उठाए सवाल

चुनावों में परेशानी मुस्लिमों को होगी क्योंकि वोटिंग की तारीखें रमजान महीने में रखी गई हैं : टीएमसी नेता

(संपूर्ण समाचार सेवा)

कोलकाता/लखनऊ,

लोकसभा चुनाव की तारीखें रविवार को घोषित कर दी गईं। इस तारीखों की घोषणा होने के साथ ही एक नया विवाद सामने आया है। तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में वोटिंग की तारीखें रमजान के महीने में पड़ रही हैं। ऐसे में मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इन तारीखों में बदलाव की मांग की है। कोलकाता के मेयर और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता फिरहाद हाकिम ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है और हम उसका सम्मान करते हैं। हम चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन सात फेज में होने वाले चुनाव बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कठिन होंगे। इतना ही नहीं, इन चुनावों में सबसे ज्यादा परेशानी मुस्लिमों को होगी क्योंकि वोटिंग की तारीखें रमजान के महीने में रखी गई हैं। वहीं बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। यदि किसी को तारीखों पर आपत्ति है तो वह चुनाव आयोग में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। उन्होंने कहा, रही बात रमजान में वोटिंग की तो आयोग ने मतदान के लिए ८ घंटे का समय रखा है। इस बीच कभी भी जाकर मतदान किया जा सकता है। विपक्षी दल चुनाव में हार के डर से अभी से बहाने ढूंढने लगे हैं। टीएमसी नेता ने कहा कि तीनों राज्यों (यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल) में अल्पसंख्यकों की आबादी बहुत ज्यादा है। मुस्लिम रोजा रखेंगे और अपना वोट भी डालेंगे यह बात चुनाव आयोग को ध्यान में रखनी चाहिए। फरहाद हाकिम ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) चाहती है कि अल्पसंख्यक अपना वोट न डाल पाएं लेकिन हम चिंतित नहीं हैं। लोग अब बीजेपी हटाओ-देश बचाओ के लिए प्रतिबद्ध हैं।वहीं दूसरी ओर इस्लामिक स्कॉलर, लखनऊ ईदगाह के इमाम और शहरकाजी मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी चुनावों की इन तारीखों पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से निवेदन किया है कि इन तारीखों को रमजान से पहले या फिर ईद के बाद रखा जाए। फिरंगी महली ने कहा, चुनाव आयोग ने यूपी में ६,१२ और १९ को भी वोट डालने का कहा है। जबकि ५ मई की रमजान मुबारक का चांद दिख सकता है ६ से रमजान का मुबारक महीना शुरू होगा। तीनो तारीखें रमजान के महीने में पड़ेंगी जिससे मुसलमानों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वह चुनाव आयोग से गुजारिश करते हैं कि चुनाव की तारीखें रमजान से पहले या ईद के बाद रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोट डालने निकलें और उन्हें कोई परेशानी न हो।

रमजान के दौरान वोटिंग पर चुनाव आयोग बोला

त्योहार का रखा ध्यान, शुक्रवार को नहीं मतदान

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

रमजान में मतदान के मुद्दे पर चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी भी शुक्रवार या त्योहार के दिन मतदान नहीं हैं। आयोग ने कहा कि रमजान के पूरे महीने ही चुनाव न हों, ऐसा नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग का यह बयान उस मौके पर आया है, जब कई पार्टियां रमजान में मतदान होने के फैसले का विरोध कर रही हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि २ जून से पहले नई सरकार का गठन होना जरूरी था। ऐसे में इसे और टाला नहीं जा सकता था। साथ ही एक महीने तक चुनाव न हों, ऐसा भी संभव नहीं था। इसलिए आयोग ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि किसी भी शुक्रवार को अथवा किसी फेस्टिवल के दौरान मतदान न हो। चुनाव आयोग का कहना है कि हमारे पास इन तारीखों को बदलने का अथवा चुनाव के समय को आगे-पीछे करने का विकल्प ही नहीं था।बता दें कि तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में वोटिंग की तारीखें रमजान के महीने में पड़ रही हैं। ऐसे में मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने इन तारीखों में बदलाव की मांग की है। कोलकाता के मेयर और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता फिरहाद हाकिम ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है और हम उसका सम्मान करते हैं। हम चुनाव आयोग के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन सात फेज में होने वाले चुनाव बिहार, यूपी और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए कठिन होंगे। उन्होंने आगे कहा कि इन चुनावों में सबसे ज्यादा परेशानी मुस्लिमों को होगी क्योंकि वोटिंग की तारीखें रमजान के महीने में रखी गई हैं। आयोग ने कहा कि रमजान के पूरे महीने ही चुनाव न हों, ऐसा नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग का यह बयान उस मौके पर आया है, जब कई पार्टियां रमजान में मतदान होने के फैसले का विरोध कर रही हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि २ जून से पहले नई सरकार का गठन होना जरूरी था। ऐसे में इसे और टाला नहीं जा सकता था। साथ ही एक महीने तक चुनाव न हों, ऐसा भी संभव नहीं था। इसलिए आयोग ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि किसी भी शुक्रवार को अथवा किसी फेस्टिवल के दौरान मतदान न हो। चुनाव आयोग का कहना है कि हमारे पास इन तारीखों को बदलने का अथवा चुनाव के समय को आगे-पीछे करने का विकल्प ही नहीं था।बता दें कि तीन राज्यों पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में वोटिंग की तारीखें रमजान के महीने में पड़ रही हैं। ऐसे में मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाया है।वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान ने भी इस फैसले का विरोध किया है।

रमजान के पूरे महीने चुनाव न हों, ऐसा नहीं हो सकता है २ जून से पहले नई सरकार का गठन जरूरी था : आयोग

पिछले कई दिनों में कई बड़े ऑपरेशन

कश्मीर : पिछले २१ दिन में १८ आतंकवादी मारे गए

(संपूर्ण समाचार सेवा) श्रीनगर,

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद सेना ने आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते २१ दिनों में कुल १८ आतंकियों को अलग-अलग मुठभेड़ में ढेर किया है। सोमवार को सेना की १५वीं कोर के जीओसी केजेएम ढिल्लन ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफफ के अधिकारियों के साथ श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि मारे गए इन २१ आतंकियों में से ८ आतंकी पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में घुसपैठ कर आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची थी। जीओसी ने कहा कि बीते कुछ दिनों में आतंक के खिलाफ बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिन्हें तमाम एजेंसियों ने सफलतापूर्वक पूरा भी किया है। आतंकियों के खिलाफ सेना का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। श्रीनगर में हुई सुरक्षाबलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलवामा एनकाउंटर की जानकारी देते हुए कश्मीर रेंज के आईजी स्वयं प्रकाश पाणी ने कहा कि रविवार को पुलवामा के पिंगलिश में हुई मुठभेड़ में सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मुदस्सिर अहमद को मार गिराया है।आईजी ने यह भी कहा कि पिंगलिश गांव में सेना का तलाश अभियान जारी है, जिसके पुरा होने के बाद अन्य जानकारियां साझा की जाएंगी। साजिश रची थी और वह बीते कुछ दिनों से कश्मीर घाटी में जैश के लिए ही काम कर रहा था। उन्होंने बताया कि मुदस्सिर और उसके साथियों के पुलवामा के पिंगलिश गांव में छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद यहां बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसमें मुदस्सिर को मार गिराया गया। मारे गए इन २१ आतंकियों में से ८ आतंकी पाकिस्तानी हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान में घुसपैठ कर आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रची थी। जीओसी ने कहा कि बीते कुछ दिनों में आतंक के खिलाफ बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिन्हें तमाम एजेंसियों ने सफलतापूर्वक पूरा भी किया है। आतंकियों के खिलाफ सेना का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। श्रीनगर में हुई सुरक्षाबलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलवामा एनकाउंटर की जानकारी देते हुए कश्मीर रेंज के आईजी स्वयं प्रकाश पाणी ने कहा कि रविवार को पुलवामा के पिंगलिश में हुई मुठभेड़ में सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मुदस्सिर अहमद को मार गिराया है। मुदस्सिर ने ही हमले की

आतंकवादियों के खिलाफ फिलहाल की गई कार्रवाई मामले में सेना अधिकारी, पुलिस द्वारा दी गई जानकारी

संपादकिय

लोकतंत्र का उत्सव- आम चुनाव की तिथियों का एलान होते ही बढ़ी देश के मतदाताओं की जिम्मेदारी

राजनीतिक दलों से यह उम्मीद है कि वे राजनीतिक शुचिता और लोकतांत्रिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए चुनाव लड़ेंगे। निर्वाचन आयोग की ओर से आम चुनाव की तिथियां तय कर देने के साथ ही देश लोकतंत्र का उत्सव मनाने की दिशा में बढ़ चला है। पिछले आम चुनाव में मतदान के नौ चरणों के मुकाबले इस बार सात चरण घोषित होने से यह तो स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग पहले के मुकाबले कुछ और समर्थ हुआ है, लेकिन उसकी कोशिश यही होनी चाहिए कि चुनाव की प्रक्रिया कम से कम लंबी हो। आज के इस तकनीकी युग में अपेक्षाकृत छोटी चुनाव प्रक्रिया के लक्ष्य को हासिल करना कठिन नहीं होना चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया न केवल यथासंभव छोटी होनी चाहिए, बल्कि वह राजनीतिक दलों और उनके प्रत्याशियों के छल–कपट से मुक्त भी होनी चाहिए। यह सही है कि पहले की तुलना में आज की चुनाव प्रक्रिया कहीं अधिक साफ–सुथरी और भरोसेमंद है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि वह बेहद खर्चीली होने के साथ ही धनबल से भी दुष्प्रभावित होने लगी है। लोकतंत्र का उत्सव- आम चुनाव की तिथियों का एलान होते ही बढ़ी देश के मतदाताओं की जिम्मेदारीविडंबना यह है कि चुनाव लड़ने वाले इस आशय का शपथपत्र देकर छुट्टी पा लेते हैं कि उन्होंने तय सीमा के अंदर ही धन खर्च किया। यह विडंबना तब है जब हर राजनीतिक दल और खुद निर्वाचन आयोग भी इससे अवगत है कि आज चुनावों में किस तरह पानी की तरह पैसा बहाया जाता है। अब तो हालत है कि पैसे बांटकर चुनाव जीत लेने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। समस्या यह है कि जहां जागरूक जनता चुनावी खामियों को दूर करने की जरूरत महसूस करती है वहीं राजनीतिक दल ऐसी किसी जरूरत पर ध्यान ही नहीं देते। यह अच्छा नहीं हुआ कि बीते पांच साल में न तो कोई ठोस राजनीतिक सुधार किया गया और न ही चुनावी सुधार। आम चुनाव को भले ही लोकतंत्र के उत्सव की संज्ञा दी जाती हो, लेकिन सच यह है कि इस उत्सव में राजनीतिक बैर भाव अपने चरम तक पहुंचता दिखता है। कई बार परस्पर विरोधी राजनीतिक दल–एक दूसरे के प्रति शत्रुवत व्यवहार करते हैं। वे न केवल अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति अशालीन–अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उन्हें बदनाम करने और नीचा दिखाने के लिए झूठ और कपट का सहारा भी लेते हैं। इसका कोई औचित्य नहीं कि आम चुनाव के मौके पर राजनीतिक विमर्श रसातल में चला जाए। दुर्भाग्य से राजनीतिक दलों से यह उम्मीद कम ही है कि वे राजनीतिक शुचिता और लोकतांत्रिक मर्यादा का ध्यान रखते हुए चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में मतदाताओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल सोच–समझकर करें। अपने देश में यह एक बीमारी सी है कि बाकी समय तो हम सब जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद को कोसते हैं, लेकिन वोट देते समय जाति–मजहब को ही महत्व दे देते हैं। जात–पांत के आधार पर राजनीति इसीलिए होती है, क्योंकि एक तबका इसी आधार पर वोट देता है। यह भी किसी से छिपा नहीं कि कई बार राष्ट्रहित के मसलों से अधिक महत्व संकीर्ण स्वार्थ को दे दिया जाता है। चूंकि आम चुनाव देश के भविष्य के साथ राजनीति की भी दशा–दिशा तय करते हैं इसलिए आम मतदाता का इस भाव से लैस होना जरूरी है कि वह वोट के जरिये एक महती काम करने जा रहा है।

दोहरे लाभ वाला कारगर कदम- कंस्ट्रक्शन में रोजगार सृजन और जरूरत मंदों को आवास

(जी.एन.एस.) बीते साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में तापमान लगभग 2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हा ? कंपा देने वाली ऐसी सर्दी में सबसे ज्यादा आफत बेघर लोगों पर ही आती है। बेरहम सर्दी से बचने के लिए उनके पास रैनबसेरों में आसरा लेने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। मगर रैनबसेरों में भी लोगों का अंबार लगा रहता है। यहां तक कि इन रैनबसेरों में भी सुविधाओं का नितांत अभाव होता है। वहां रहने वालों को भी बहुत संघर्ष करना प ?ता है, लेकिन उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके लिए किराये पर घर लेना संभव नहीं है। जब राजधानी दिल्ली की स्थिति ऐसी है तो फिर दूरदराज के इलाकों के हालात की बस कल्पना ही की जा सकती है। वहां तो रैनबसेरों का कोई अस्तित्व ही नहीं दिखेगा। इसकी वजह से भीषण गर्मी या सर्दी के प्रतिकूल मौसम में तमाम लोगों की मौत तक हो जाती है। भारत में लोगों के पास घर न होना एक बडी समस्या है। अधिकांश अनुमानों के अनुसार भारत में करीब दो करोड घरों की कमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त, 2015 को लालकिले की प्राचीर से एलान किया था कि वर्ष 2022 तक देश में प्रत्येक व्यक्ति को मकान उपलब्ध कराया जाएगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें किफायती मकानों के निर्माण से लेकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ब्याज दरों में छूट दी जा रही है। सरकार की तमाम योजनाओं और उन्हें सिरे च ?ने के लिए किए जा रहे गंभीर प्रयासों से इस लक्ष्य प्राप्ति में उसकी ईमानदारी झलकती है। केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंक ?ों के अनुसार वित्त वर्ष 2018–19 की तीसरी तिमाही में योजना के तहत 72.66 लाख मकानों को मंजूरी दी गई। योजना के तहत काफी संख्या में मकानों का निर्माण हो चुका है और उनमें से तमाम मकान लोगों को आवंटित भी हो चुके हैं। प्रत्येक बेघर और आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को मकान जैसी सुविधा उपलब्ध कराने से उनका जीवन स्तर बेहतर होगा, उनके जीवन में खुशियां ब ?ंगी और इसका सीधा असर बेहतर उत्पादकता में भी नजर आएगा। वहीं यह भी एक सकारात्मक पहलू है कि मकानों की कमी में अंतर की भरपाई के लिए होने वाली इस कवायद से जुडी गतिविधियों के कारण सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी को रफ्तार मिलेगी और बडे पैमाने पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। भारत में कृषि के बाद भवन निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन ही सबसे बडा रोजगारप्रदाता क्षेत्र है। इसमें कच्ची सामग्री से लेकर विनिर्मित उत्पादों से संबंधित करीब 269 छोटे–ब ? उद्योग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जु ? हुए हैं। इसमें इस्पात, सीमेंट, पेंट, फर्नीचर से लेकर तमाम छोटे उद्योगों के उत्पादों की ब ?ी भूमिका होती है। अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले 14 ब ? उद्योगों की सूची में कंस्ट्रक्शन तीसरे पायदान पर आता है। कंस्ट्रक्शन में निवेश होने वाले प्रति एक रुपये से जीडीपी में 78 पैसों का जुडाव होता है। अर्थव्यवस्था पर गुणात्मक प्रभाव के मामले में भी कंस्ट्रक्शन परिवहन एवं कृषि जैसे क्षेत्रों की तुलना में कहीं आगे है और इस पैमाने पर चौथे स्थान पर आता है। परंपरागत रूप से कंस्ट्रक्शन असंगठित, छितरा हुआ और टुकों में बंटा हुआ डकारोबार रहा है जिसे संगठित करने की कवायद में सामने आनी वाली संक्रमणकालीन चुनौतियों के चलते इसकी रफ्तार कुछ सुस्त प ? गई है। निर्माण गतिविधियों में आए इस ठहराव से रोजगार के अवसरों पर भी बुरा असर पडा। हालांकि सुधारों की यह प्रक्रिया लगभग आकार ले चुकी है और यह उद्योग भी अब इससे संभलकर फिर से रफ्तार पकड रहा है। असल में कंस्ट्रक्शन उद्योग से जड सभी अंशभागियों जैसे निवेशकों, खरीदारों और कर्जदाताओं सभी के हितों को सुरक्षित रखने के लिए ये सुधार अपरिहार्य ही नहीं अनिवार्य हो चले थे। इन सुधारों से ही प्रत्येक परिवार के लिए घर के राष्ट्रीय सपने का साकार होना संभव है। सुधारों की प्रक्रिया में महसूस हुआ कुछ दर्द भी ऊंची वृद्धि के मरहम से जल्द ही हवा होने वाला है। इससे आर्थिक समृद्धि के नए द्वार खुलेंगे। दुनिया को हतप्रभ कर देने वाली चीन की तेज रफ्तार आर्थिक वृद्धि में कंस्ट्रक्शन उद्योग की बेहद अहम भूमिका रही है। वास्तव में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की चीन के जीडीपी में 15 प्रतिशत और कुल रोजगार में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एक अनुमान पर गौर करें तो 50 लाख लोगों के लिए घर जीडीपी में कम से कम एक प्रतिशत का इजाफा कर सकते हैं। केवल कंस्ट्रक्शन उद्योग में ही सालाना 50 लाख लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। कंस्ट्रक्शन के विभिन्न स्तरों पर लगे कामगारों के अलावा प्रॉपर्टी सलाहकारों से लेकर होम डेकोरेटर्स जैसे तमाम पेशेवरों के लिए इससे रोजगार मिलेगा। कंस्ट्रक्शन को अक्सर 'घरेलू वृद्धि का इंजन' भी कहा जाता है। हालांकि इस लक्ष्य को हासिल करने में आने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। कंस्ट्रक्शन गतिविधियों की स्वीकृति के लिए सिंगल विंडो वाली व्यवस्था बनानी होगी। कर्ज के लिए आसान और लचीली व्यवस्था बनाकर उसे प्रभावी रूप से लागू करना होगा। निजी क्षेत्र को करों में कुछ छूट भी देनी होगी। इसके अलावा निजी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लिए व्यावसायिक पैमाने पर नई रणनीतिक विचार प्रक्रिया भी विकसित करनी होगी ताकि उन्हें वित्तीय संसाधन सुलभ हों। इसमें उन्हें दिए गए कर्ज की वापसी और ब्याज की अदायगी भी सुनिश्चित करनी होगी। वास्तव में वाणिज्यिक बैंकों, गैर–बैंकिंग वित्तीय संस्थानों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को एक अलग श्रेणी बनाकर कंस्ट्रक्शन उद्योग को कर्ज देने के मामले में दीर्घावधिक देनदारी का खाका तैयार करना चाहिए। फिलहाल इसमें कंपनियों को तीन साल तो उपभोक्ताओं को 20 साल की मियाद मिलती है। इससे कर्जदाताओं के लिए परिसंपत्ति–देनदारी की गुत्थी सुलझ जाएगी और उनकी आगे की राह आसान होगी। वास्तव में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की चीन के जीडीपी में 15 प्रतिशत और कुल रोजगार में 20 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। रेरा, जीएसटी और आरईआइटी जैसे तमाम सुधारों में कंस्ट्रक्शन उद्योग को वह शक्ति देने की क्षमता है जिसमें वे विकसित देशों की कंपनियों की तर्ज पर काम कर सकती हैं। हालांकि तेज वृद्धि के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कोशिशों के बीच बेहतर समन्वय के लिए शुरुआती प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी। शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय ने एक लक्ष्य तय कर लिया है जिसमें सभी अंशभागियों के हितों को ध्यान में रखते हुए गंभीरता के साथ आगे बडना होगा।

आम पाकिस्तानी भारत जैसा लोकतंत्र चाहते हैं, देश रक्तपात और सेना प्रायोजित आतंकवाद से नहीं चलत

(जी.एन.एस.) कृत्रिम में प्राकृतिक सौंदर्य नहीं होता। अप्राकृतिक में प्राकृतिक गुणसूत्र नहीं होते। राष्ट्र गठन का आधार सांस्कृतिक तत्व होते हैं। पाकिस्तान स्वाभाविक राष्ट्र नहीं है। पुलवामा और बालाकोट की घटनाओं के बाद पाकिस्तान की मानसिकता अंतरराष्ट्रीय विवेचन का विषय बनी है। भारत में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान 1947 तक भारत था। इसके पहले यह भाग ब्रिटिश सत्ता में था। अतीत में यह मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य का भी भाग था। यह सिंधु सभ्यता का क्षेत्र था। अभी दो वर्ष पहले पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र में बख्शाली गांव से बख्शाली लिपि में लिखित शून्य की जानकारी मिली थी। भारत को इस प्राचीन ज्ञान पर गर्व है। भारतीय दर्शन एवं ज्ञान शोध के तमाम भू–भाग अब पाकिस्तान में हैं। दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक है। कौटिल्य वहीं आचार्य थे। यहां भारत के मन को आनंद देने वाली सिंधु नदी का क्षेत्र भी है। मूलभूत प्रश्न है कि ऐसी प्राचीन भारतीय विरासत के बावजूद पाकिस्तान की मानसिकता भारत विरोधी क्यों है ? वह भारत जैसा होने को बेताब है, लेकिन उसके मन की भारत विरोधी ग्रंथि उसे आत्महत्या के लिए उकसाया करती है। आखिर उसे अपने मुल्क की बेहतरी की चिंता क्यों नहीं है ? भारत को ही नीचा दिखाने की मानसिकता का रहस्य क्या है ? पंथ, मजहब की बुनियाद पर राष्ट्र नहीं बनते। मौलाना मौदूदी इस्लामी विद्वान ने 'मसल्लम कौमियत' में लिखा था, 'जहां इस्लाम है, वहां राष्ट्रीयता के लिए कोई जगह नहीं।' स्वाधीनता संग्राम में मुस्लिम मित्रों की कम भागीदारी से गांधी जी चिंतित थे। 'हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट' के उद्धरण में मौदूदी के मुताबिक 'मुसलमान भी भारत की आजादी के उतने ही इच्छुक थे, जितने बाकी लोग, लेकिन वे इसे एक प ?ाव मानते थे।' एफके दुर्रानी ने 'मीनिंग ऑफ पाकिस्तान' में इसका खुलासा किया, 'पाकिस्तान का निर्माण इसलिए जरूरी था कि इसे शिविर बनाकर शेष भारत का इस्लामीकरण किया जाए।ुस्लिम लीग मजहबी आधार पर अलग मुल्क मांग रही थी। उसकी मुहिम में लाखों गैर–मुस्लिम मारे गए थे। खूब रक्तपात हुआ। फिर देश बंट गया। भारत ने नवंबर 1949 में संविधान बनाया। पाकिस्तान का संविधान सात साल बाद 1956 में बना। पाकिस्तान ने स्वयं को इस्लामी गणराज्य घोषित किया। पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू के सवाल पर आंदोलन हुआ। इसे कुचलने के लिए 'सर्चलाइट ऑपरेशन' हुआ। लाखों मारे गए। भारत ने हस्तक्षेप किया। पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना। देश रक्तपात और सेना प्रायोजित आतंकवाद से नहीं चलते। पाकिस्तान ने 1973 में नया संविधान बनाया। भारतीय संस्कृति की विरासत न 1956 के संविधान में थी और न ही 1973 के नए संविधान में। 1956 के संविधान में यह इस्लामी गणतंत्र था। 1973 में नई बात जु ?ी कि सभी कानून कुरान के अनुसार बनाए जाएंगे। पाकिस्तान भारत की बराबरी चाहता है। भारत में अटल जी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण हुआ। यह आत्मरक्षा आवश्यकता थी। देखा–देखी पाकिस्तान ने भी किया। लेबनानी विद्वान खलील जिब्रान ने मजेदार बात लिखी थी, 'मेंढक बैलों की तुलना में भले ही अधिक शोर कर लें, लेकिन वे न तो हल खींच सकते हैं और न ही कोल्हू का चक्र हिला सकते हैं।' पाकिस्तानी नेता अक्सर भारत को परमाणु बम की धमकी देते हैं कि तब यहां न चिचिया बोलेगी और न मंदिर की घंटिया बजेंगी। भारत ने परमाणु धमकी कभी नहीं दी कि तब पाकिस्तान में न अजान होगी और न ही आतंकी ट्रेनिंग स्कूल चलेंगे। पाकिस्तान भारत विरोधी ग्रंथि के चलते बम और युद्ध की धमकियां देता है। आम पाकिस्तानी भारत जैसी समृद्धि और भारत जैसा लोकतांत्रिक समाज चाहते हैं, लेकिन भारत विरोधी ग्रंथि उसे चैन से नहीं बैठने देती। पाकिस्तानी मानसिकता में हिंदू समाज के प्रति घृणा है। पाकिस्तान में घृणा भाव की तालीम भी दी जाती है। एक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जेडए भुट्टो के सलाहकार रहे खुर्शीद कमाल अजीज 'इतिहास का कत्ल' में लिखते हैं, '1965 और 1971 के युद्धों को पाकिस्तान की विजय के रूप में दर्शाया गया। पुस्तकें छात्रों में भारत औंर हिंदुओं के प्रति घृणाभाव उत्पन्न करने के लिए तैयार होती हैं। हिंदू धर्म और संस्कृति का पक्षपातपूर्ण वर्णन, तिरस्कार और यह दावा कि विभाजन के वक्त और उसके बाद सांप्रदायिक दंगे केवल हिंदुओं, सिखों द्वारा फैलाए गए थे। मुसलमान कहीं भी आक्रमणकारी नहीं थे।' अजीज ने पाठ्य पुस्तक 'मुआशाराती' से उद्धरण दिए, 'राजा जयपाल ने महमूद गजनवी के मुल्क में घुसने की कोशिश की। इस पर गजनवी ने जयपाल को हरा दिया। लाहौर हथिया लिया।' पाकिस्तानी स्वयं पर ही हमलावर रहे मोहम्मद बिन कासिम, गोरी, गजनी को हमलावर नहीं मानते। वे अपनी मिसाइलों का नाम उन पर रखते हैं। हमलावरों के प्रति ऐसी मोहब्बत को क्या कहें ? यूरोप में इसे 'स्टाकहोम सिंड्रोम' कहते हैं। स्टाकहोम में अपहर्ताओं के चंगुल में फंसी युवती उन्हीं को दिल दे बैठी थी। पाकिस्तानी मानस को भारत घृणा के रसायन से विषाक्त किया गया है। पूर्व राजनयिक जेएन दीक्षित ने लिखा, 'भारत विभाजन का उद्देश्य हिंदू क्षेत्रों को छोटे राजनीतिक भूभागों में बांटना एवं उपमहाद्वीप में सबसे बडी राजनीतिक शक्ति के रूप में पाकिस्तान बनाना था। पाकिस्तान का अंतिम लक्ष्य भारत विखंडन है। भारत सभी युद्धों में पाकिस्तान को हराने के बावजूद उसके प्रति उदार रहा, लेकिन पाकिस्तानी सत्ता भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण रखती है।' वहां यहीं नीतिगत निरंतरता है। हाल में पाकिस्तानी पंजाब के मंत्री फैयाजुल हसन चौहान ने हिंदुओं को अपशब्द कहे। इस पर विवाद के बाद उन्हें इस्तीफा देना प ?ा। उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन मूल प्रश्न उनकी मानसिकता का है जो निजी नहीं है। वह पाक की भारत विरोधी ग्रंथि का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पाक विघटन के कगार पर है। पाकिस्तान बनने के कुछ समय बाद ही पठान, बलूच, पंजाबी, पख्तून, सिंधी, मोहाजिर समूह पीि?त महसूस करने लगे थे। शिया, सुन्नी, इस्माइली, दाऊदी बोहरा के टकराव भी सतह पर हैं। पुराना आरोप स्थायी है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को धोखे से मिलाया। 1958, 1963 से 1969 और 2004 में तमाम आंदोलन हुए थे। अब भी जारी हैं। बलूच स्वतंत्र सांस्कृतिक अस्मिता है। पाक ने बलूचिस्तान आंदोलन को कुचलने के लिए वायु सेना का भी दुरुपयोग किया है। वास्तविक राष्ट्र अपने नागरिकों के विरुद्ध सेना का प्रयोग नहीं करते, लेकिन पाक में दमन के सभी रास्ते जायज हैं। यह सिंधु सभ्यता का क्षेत्र था। अभी दो वर्ष पहले पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र में बख्शाली गांव से बख्शाली लिपि में लिखित शून्य की जानकारी मिली थी। भारत को इस प्राचीन ज्ञान पर गर्व है। भारतीय दर्शन एवं ज्ञान शोध के तमाम भू–भाग अब पाकिस्तान में हैं। दुनिया का प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला भारतीय स्वाभिमान का प्रतीक है। कौटिल्य वहीं आचार्य थे। यहां भारत के मन को आनंद देने वाली सिंधु नदी का क्षेत्र भी है। मूलभूत प्रश्न है कि ऐसी प्राचीन भारतीय विरासत के बावजूद पाकिस्तान की मानसिकता भारत विरोधी क्यों है ? वह भारत जैसा होने को बेताब है, लेकिन उसके मन की भारत विरोधी ग्रंथि उसे आत्महत्या के लिए उकसाया करती है। आखिर उसे अपने मुल्क की बेहतरी की चिंता क्यों नहीं है ? भारत को ही नीचा दिखाने की मानसिकता का रहस्य क्या है ? पंथ, मजहब की बुनियाद पर राष्ट्र नहीं बनते। मौलाना मौदूदी इस्लामी विद्वान ने 'मसल्लम कौमियत' में लिखा था, 'जहां इस्लाम है, वहां राष्ट्रीयता के लिए कोई जगह नहीं।' स्वाधीनता संग्राम में मुस्लिम मित्रों की कम भागीदारी से गांधी जी चिंतित थे। 'हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट' के उद्धरण में मौदूदी के मुताबिक 'मुसलमान भी भारत की आजादी के उतने ही इच्छुक थे, जितने बाकी लोग, लेकिन वे इसे एक प ?ाव मानते थे।' एफके दुर्रानी ने 'मीनिंग ऑफ पाकिस्तान' में इसका खुलासा किया, 'पाकिस्तान का निर्माण इसलिए जरूरी था कि इसे शिविर बनाकर शेष भारत का इस्लामीकरण किया जाए।ुस्लिम लीग मजहबी आधार पर अलग मुल्क मांग रही थी। उसकी मुहिम में लाखों गैर–मुस्लिम मारे गए थे। खूब रक्तपात हुआ। फिर देश बंट गया। भारत ने नवंबर 1949 में संविधान बनाया। पाकिस्तान का संविधान सात साल बाद 1956 में बना। पाकिस्तान ने स्वयं को इस्लामी गणराज्य घोषित किया। पूर्वी पाकिस्तान में उर्दू के सवाल पर आंदोलन हुआ। इसे कुचलने के लिए 'सर्चलाइट ऑपरेशन' हुआ। लाखों मारे गए। भारत ने हस्तक्षेप किया। पूर्वी पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना। देश रक्तपात और सेना प्रायोजित आतंकवाद से नहीं चलते। पाकिस्तान ने 1973 में नया संविधान बनाया। भारतीय संस्कृति की विरासत न 1956 के संविधान में थी और न ही 1973 के नए संविधान में। 1956 के संविधान में यह इस्लामी गणतंत्र था। 1973 में नई बात जु ?ी कि सभी कानून कुरान के अनुसार बनाए जाएंगे। पाकिस्तान भारत की बराबरी चाहता है। भारत में अटल जी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण हुआ। यह आत्मरक्षा आवश्यकता थी। देखा–देखी पाकिस्तान ने भी किया। लेबनानी विद्वान खलील जिब्रान ने मजेदार बात लिखी थी, 'मेंढक बैलों की तुलना में भले ही अधिक शोर कर लें, लेकिन वे न तो हल खींच सकते हैं और न ही कोल्हू का चक्र हिला सकते हैं।' पाकिस्तानी नेता अक्सर भारत को परमाणु बम की धमकी देते हैं कि तब यहां न चिि?या बोलेगी और न मंदिर की घंटिया बजेंगी। नागरिक स्वतंत्रता समाप्त हो रही है। ईशनिंदा कानून की तलवारें हैं। कोर्ट के निर्णय भी नहीं माने जाते। फौज और आइएसआइ ही असली शासक हैं। भारत ने परमाणु धमकी कभी नहीं दी कि तब पाकिस्तान में न अजान होगी और न ही आतंकी ट्रेनिंग स्कूल चलेंगे। पाकिस्तान भारत विरोधी ग्रंथि के चलते बम और युद्ध की धमकियां देता है। आम पाकिस्तानी भारत जैसी समृद्धि और भारत जैसा लोकतांत्रिक समाज चाहते हैं, लेकिन भारत विरोधी ग्रंथि उसे चैन से नहीं बैठने देती। पाकिस्तानी मानसिकता में हिंदू समाज के प्रति घृणा है। पाकिस्तान में घृणा भाव की तालीम भी दी जाती है। एक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जेडए भुट्टो के सलाहकार रहे खुर्शीद कमाल अजीज 'इतिहास का कत्ल' में लिखते हैं, '1965 और 1971 के युद्धों को पाकिस्तान की विजय के रूप में दर्शाया गया। पुस्तकें छात्रों में भारत औंर हिंदुओं के प्रति घृणाभाव उत्पन्न करने के लिए तैयार होती हैं। हिंदू धर्म और संस्कृति का पक्षपातपूर्ण वर्णन, तिरस्कार और यह दावा कि विभाजन के वक्त और उसके बाद सांप्रदायिक दंगे केवल हिंदुओं, सिखों द्वारा फैलाए गए थे। मुसलमान कहीं भी आक्रमणकारी नहीं थे।' अजीज ने पाठ्य पुस्तक 'मुआशाराती' से उद्धरण दिए, 'राजा जयपाल ने महमूद गजनवी के मुल्क में घुसने की कोशिश की। इस पर गजनवी ने जयपाल को हरा दिया। लाहौर हथिया लिया।' पाकिस्तानी स्वयं पर ही हमलावर रहे मोहम्मद बिन कासिम, गोरी, गजनी को हमलावर नहीं मानते। वे अपनी मिसाइलों का नाम उन पर रखते हैं। हमलावरों के प्रति ऐसी मोहब्बत को क्या कहें ? यूरोप में इसे 'स्टाकहोम सिंड्रोम' कहते हैं। स्टाकहोम में अपहर्ताओं के चंगुल में फंसी युवती उन्हीं को दिल दे बैठी थी। पाकिस्तानी मानस को भारत घृणा के रसायन से विषाक्त किया गया है। पूर्व राजनयिक जेएन दीक्षित ने लिखा, 'भारत विभाजन का उद्देश्य हिंदू क्षेत्रों को छोटे राजनीतिक भूभागों में बांटना एवं उपमहाद्वीप में सबसे बडी राजनीतिक शक्ति के रूप में पाकिस्तान बनाना था। पाकिस्तान का अंतिम लक्ष्य भारत विखंडन है। भारत सभी युद्धों में पाकिस्तान को हराने के बावजूद उसके प्रति उदार रहा, लेकिन पाकिस्तानी सत्ता भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण रखती है।' वहां यहीं नीतिगत निरंतरता है। हाल में पाकिस्तानी पंजाब के मंत्री फैयाजुल हसन चौहान ने हिंदुओं को अपशब्द कहे। इस पर विवाद के बाद उन्हें इस्तीफा देना प ?ा। उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन मूल प्रश्न उनकी मानसिकता का है जो निजी नहीं है। वह पाक की भारत विरोधी ग्रंथि का ही प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पाक विघटन के कगार पर है। पाकिस्तान बनने के कुछ समय बाद ही पठान, बलूच, पंजाबी, पख्तून, सिंधी, मोहाजिर समूह पीि?त महसूस करने लगे थे। शिया, सुन्नी, इस्माइली, दाऊदी बोहरा के टकराव भी सतह पर हैं। पुराना आरोप स्थायी है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को धोखे से मिलाया। 1958, 1963 से 1969 और 2004 में तमाम आंदोलन हुए थे। अब भी जारी हैं। बलूच स्वतंत्र सांस्कृतिक अस्मिता है। पाक ने बलूचिस्तान आंदोलन को कुचलने के लिए वायु सेना का भी दुरुपयोग किया है। वास्तविक राष्ट्र अपने नागरिकों के विरुद्ध सेना का प्रयोग नहीं करते, लेकिन पाक में दमन के सभी रास्ते जायज हैं। यह सिंधु सभ्यता का क्षेत्र था। अभी दो वर्ष पहले पाकिस्तान के पेशावर क्षेत्र में बख्शाली गांव से बख्शाली लिपि में लिखित शून्य की जानकारी मिली थी। भारत को इस प्राचीन ज्ञान पर गर्व है। भारतीय दर्शन एवं ज्ञान शोध के तमाम भू–भाग अब पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान आतंकवादी प्रशिक्षण का विश्वविद्यालय है। आतंकी भारत आकर रक्तपात करते हैं। पाकिस्तान सुबूत मांगता है। सुबूत दिए भी जाते हैं। वार्ता की पेशकश होती है। मोदी के नेतृत्व में इस दफा की 'वार्ता' वायुसेना ने की। बालाकोट की वारदात पाकिस्तानी भाषा वाली वार्ता ही थी। देश प्रसन्न है। इसी भाषा से पाकिस्तान की भारत विरोधी ग्रंथि का उपचार होगा।

पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद एवं पटना तथा गांधीधाम एवं भागलपुर स्टेशनों के बीच तीन त्योहार विशेष ट्रेनें

आगामी होली के अवकाश दौरान यात्रियों की बेहतर सुविधा तथा इस सीज़न के दौरान यात्रियों द्वारा की गई विशेष ट्रेनों की मांग के मद्देनज़र पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद एवं पटना तथा गांधीधाम एवं भागलपुर स्टेशनों के बीच दो त्योहार विशेष ट्रेनें विशेष किराये के साथ चलाने का निर्णय लिया गया है। ट्रेन सं. 09421 अहमदाबाद–पटना विशेष ट्रेन अहमदाबाद से सोमवार, 18 मार्च, 2019 को 23.25 बजे प्रस्थान करेगी और बुधवार को 08.45 बजे पटना पहुँचेगी। इसी प्रकार वापसी में ट्रेन सं. 09422 पटना–अहमदाबाद विशेष ट्रेन बुधवार, 20 मार्च, 2019 को पटना से 11.00 बजे प्रस्थान करेगी और अगले दिन 19.00 बजे अहमदाबाद पहुँचेगी। इस ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, शयनयान तथा द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे होंगे। यह ट्रेन यात्रा के दौरान दोनों दिशाओं में नडियाद, गोधरा, दाहोद, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, आगरा फोर्ट, टुंडला, कानपुर, इलाहाबाद, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर, आरा तथा दानापुर स्टेशनों पर रुकेगी। ट्रेन सं. 09451/09452 गांधीधाम–भागलपुर साप्ताहिक विशेष ट्रेन विशेष किराये के साथ ट्रेन सं. 09451 गांधीधाम–भागलपुर विशेष ट्रेन शुक्रवार, 15 मार्च, 2019 को गांधीधाम से 17.40 बजे रवाना होगी एवं रविवार, 17 मार्च, 2019 को 18.00 बजे भागलपुर पहुँचेगी। इसी प्रकार वापसी यात्रा में ट्रेन सं 09452 भागलपुर–गांधीधाम विशेष ट्रेन सोमवार, 18 मार्च, 2019 को भागलपुर से 06.30 बजे रवाना होगी एवं बुधवार, 20 मार्च, 2019 को 08.00 बजे गांधीधाम पहुँचेगी। इस ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, शयनयान तथा द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे होंगे। यात्रा के दौरान यइ ट्रेन दोनों दिशाओं में भचाऊ, समाखियाली, ध्रांगध्रा, अहमदाबाद, नडियाड, दाहोद, रतलाम, भवानी मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना, भरतपुर, अछनेरा, मथुरा, कासगंज, फर्रुखाबाद, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, सिवान, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, बेगूसराय, साहिबपुर कमल, मुंगेर तथा सुल्तानगंज स्टेशनों पर ठहरेगी। ट्रेन सं. 09421 एवं 09451 की बुकिंग 13 मार्च, 2019 से सभी यात्री आरक्षण केन्द्रों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर प्रारम्भ होगी।

रूपाणी द्वारा नवनियुक्त मंत्रियों को पद दिया गया

जवाहर चावड़ा को प्रवासन, मत्स्योद्योग पद का हवाला

मंत्री योगेश पटेल को शहरी गृह निर्माण, धर्मेन्द्रसिंह जडेजा को अन्न और नागरिक पुरवठा विभाग की जवाबदारी

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

रूपाणी सरकार ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडलका विस्तार किया था और नवनियुक्त तीन मंत्रियों को आज मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा विधिवत रुप से पद दिया गया। जिस में कांग्रेस में भाजपा में शामिल हुए और सीधे ही केबिनेट मिनिस्टर बनाये गए जवाहर चावड़ा को प्रवासन और मत्स्योद्योग विभाग का हवाला सौंपा गया। जबकि मंत्री योगेश पटेल को नर्मदा और शहरी गृह निर्माण और धर्मेन्द्रसिंह जडेजा को अन्न और नागरिक पुरवठा, ग्राहक सुरक्षा और कुटिर उद्योग राज्यकक्षा के विभाग दिया गया। राज्य मंत्री वासणभाई आहीर को प्रवासन विभाग का राज्यकक्षा का हवाला भी दिया गया। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के द्वारा गुजरात ऐग्रो इन्डस्ट्रीज लि. के अध्यक्ष के तौर पर वाघोडिया के मधुभाई श्रीवास्तव की नियुक्ति की गई। जबकि महाराजा कृष्णकुमारसिंहजी युनिवर्सिटी, भावनगर के वाइस चान्सेलर के रुप में महिपतसिंह चावडा की नियुक्ति की गई। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शनिवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया जिसमें तीन सदस्यों को शामिल किया गया था। इनमें कांग्रेस छोड़कर आये जवाहर चावड़ा को मंत्री पद का ईनाम मिला है, जिन्होंने एक दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। वडोदरा जिले के मांजलपुर से भाजपा विधायक योगेश पटेल और जामनगर पश्चिम से विधायक धर्मेंद्र सिंह जडेजा को भी मंत्री बनाया गया है। जडेजा भी कांग्रेस से आये थे। गुजरात के राज्यपाल ओ पी कोहली ने उन्हें पद की शपथ दिलायी थी। मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्रियों की संख्या २४ हो गई है।

फिर एक बार मोदी सरकार का दिया नारा

चुनाव का बिगुल बजते ही पीएम मोदी ने मांगा आशीर्वाद

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

चुनाव आयोग की ओर से आम चुनाव का ऐलान होने के साथ ही पीएम नरेन्द्र मोदी ने जनता से समर्थन मांगना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने लगातर कई ट्वीट कर एक बार फिर से फिर से मोदी सरकार को चुनने की अपील की। उन्होंने ट्वीट किया, सबका साथ, सबका विकास की नीति के तहत चलने वाले एनडीए को आपके आशीर्वाद की जरूरत है। अपने ५ साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमने ५ साल उन जरूरतों को पूरा करने में बिताया है, जिन्हें बीते ७० सालों में पूरा नहीं किया गया था। अब समय आ गया है कि भारत को एक समृद्ध और सुरक्षित राष्ट्र बनाने के रास्ते पर चला जाए। पीएम मोदी ने फिर एक बार मोदी सरकार हैशटैग के साथ ट्वीट कर आशीर्वाद मांगा। पीएम मोदी ने लोगों से ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र का उत्सव आ गया है। मैं देशवासियों से कहना चाहूंगा कि वे अपनी सक्रिय भागीदारी से चुनावों को मजबूत बनाएं। मुझे इस चुनाव में ऐतिहासिक मतदान की उम्मीद है। पीएम मोदी ने पहली बार वोट डालने वाले लोगों से कहा कि वे रेकॉर्ड तोड़ संख्या में मतदान करें। पीएम मोदी ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए ट्वीट किया, पहली बार देश में २.५ करोड़ परिवारों तक बिजली उपलब्ध हुई है। ७ करोड़ घरों तक रसोई गैस उपलब्ध हुई है। १.५ करोड़ परिवारों को अपना घर मिला है। पीएम मोदी ने आयुष्मान स्कीम समेत अन्य योजनाओं का जिक्र करते हुए लिखा, ५० करोड़ लोगों तक स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाओं की पहुंच। ४२ करोड़ असंगठित क्षेत्र के वृद्ध लोगों को वृद्धावस्था पेंशन। १२ करोड़ किसानों को प्रति साल ६,००० रुपये की सहायता जैसी योजनाएं जारी हुई हैं। करोड़ों परिवारों को इनकम टैक्स में छूट दी जाएगी।

प्रक्रिया को स्वचालित बनाने पर तैयारी

नौकरी बदलने पर खुद ट्रांसफर हो जाएगा पीएफ

EPFO को हर साल ईपीएफ स्थानांतरण के करीब ८ लाख आवेदन मिलते हैं : सुविधा अगले साल से शुरू

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को अगले वित्त वर्ष से नौकरी बदलने पर ईपीएफ राशि स्थानांतरण करने का अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रक्रिया को स्वचालित बनाने पर काम चल रहा है। श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। अभी ईपीएफओ के सदस्यों को यूनियन अकाउंट नंबर (यूएएन) रखने के बाद भी ईपीएफ स्थानांतरण करने के लिए अलग से अनुरोध करना पड़ता है। EPFO को हर साल ईपीएफ स्थानांतरण करने के करीब आठ लाख आवेदन मिलते हैं। श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'ईपीएफओ प्रायोगिक आधार पर नौकरी बदलने पर ईपीएफ के स्वत: हस्तांतरण पर काम कर रहा है। सभी सदस्यों के लिए सह सुविधा अगले साल किसी भी समय शुरू की जा सकती है। अधिकारी ने कहा, ईपीएफओ ने पेपरलेस संगठन बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रक्रिया की स्टडी का काम सी-डैक को दिया है। अभी ८० प्रतिशत कार्य ऑनलाइन हो रहे हैं। लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में नौकरी बदलने पर ईपीएफ का स्वत: हस्तांतरण महत्वपूर्ण है। अधिकारी ने कहा कि जैसे ही नए नियोक्ता मासिक ईपीएफ रिटर्न दायर करेंगे जिसमें नये कर्मचारी का यूएएन भी शामिल होगा, वैसे ही पहले के ईपीएफ योगदान और उसपर मिले ब्याज का स्वत: हस्तांतरण हो जाएगा। उन्होंने कहा, नौकरी बदलने पर ईपीएफ का स्वत: हस्तांतरण होने पर सदस्यों को काफी लाभ होगा क्योंकि यूएएन एक बैंक खाते की तरह हो जाएगा। इससे कोई अंत नहीं पड़ेगा कि सदस्य जगह या नियोक्ता बदलता है, ईपीएफ में वह अपना योगदान यूएएन के जरिये हासिल कर सकेंगे। यह कर्मचारियों के पूरे जीवन के दौरान लागू रहेगा।

चुनाव में सोशल मीडिया पर पैनी नजर

उम्मीदवारों को नामांकन के दौरान देना होगा ब्योरा

इस बार १०० फीसदी ईवीएम में वीवीपैट की सुविधा ताकि वोटर जान सकें कि वोट सही जगह गया या नहीं

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

बीते आम चुनाव के मुकाबले इस बार के इलेक्शन में काफी बदलाव दिखेंगे। इस बार १०० फीसदी ईवीएम में वीवीपैट की सुविधा रहेगी ताकि वोटर यह जान सकें कि उनका वोट सही जगह गया है या नहीं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी चुनाव आयोग ने कड़ी निगरानी का फैसला लिया है। इसकी जानकारी देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, सभी उम्मीदवारों को अपना नामांकन दाखिल करते वक्त अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का ब्योरा चुनाव आयोग को सौंपना होगा। चुनाव आयुक्तने कहा, सोशल मीडिया पर जारी होने वाले सभी राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पहले से मंजूरी लेनी होगी। यही नहीं चुनाव आयोग ने गूगल, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब से राजनीतिक दलों से मिलने वाले विज्ञापनों का वेरिफिक्केशन करने को कहा है। असल में इसके जरिए चुनाव आयोग किसी भी तरग के प्रॉपेगेंडा मैटिरियल पर रोक लगाना चाहता है। यही नहीं सोशल मीडिया पर प्लैटफॉर्म्स पर जारी विज्ञापनों से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए एक अधिकारी भी नियुक्तकिया जाएगा। अरोड़ा ने कहा, सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर जारी विज्ञापनों के खर्च को उम्मीदवारों के कुल खर्च में जोड़ा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्तने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों ने चुनाव के दौरान हेट स्पीच जैसी सामग्री रोक लगाने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने सुरक्षा कर्मियों की तस्वीरों को प्रचार सामग्री में इस्तेमाल न करने की हिदायत दी है। पिछले दिनों एयर फोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन की तस्वीर को एक होर्डिंग में इस्तेमाल किए जाने के बाद आयोग ने यह हिदायत दी है।

चुनाव के ऐलान पर बोली कांग्रेस

मोदी के विदाई पर्व की हुई शुरुआत : कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

आम चुनावों की तारीखों के ऐलान को कांग्रेस ने पीएम मोदी के विदाई पर्व का पहला दिन करार दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने चुनाव तारीखों के ऐलान को लेकर कहा, यह मोदी जी की विदाई पार्टी का पहला दिन है। मतदाता तैयार हैं। खेड़ा ने कहा, किसान, बेरोजगार युवा और छोटे कारोबारी, ये सभी लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे। किसान, बेरोजगार युवा और छोटे कारोबारी, ये सभी लोग इस दिन का ही इंतजार कर रहे थे : पवन खेड़ाहम नहीं जानते कि मोदी जी ने इसमें देरी क्यों की। शायद वह कांग्रेस के शासन में शुरू हुई परियोजनाओं का फीता काटना चाहते थे। यही नहीं कांग्रेस ने चुनाव की तारीखों का ऐलान होने पर एक विडियो भी ट्वीट किया गया है। बैकग्राउंड में आरंभ है प्रचंड' गाने के साथ तैयार इस विडियो में राहुल गांधी के भाषणों और रैलियों को कवर किया गया है। कांग्रेस ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए शासन को झूठा करार देते हुए लिखा, बिगुल बजा है, अब जनता की बारी है। झूठ से लड़ने की, पुरजोर तैयारी है। कांग्रेस हैशटैग जीत होगी सच की के साथ यह ट्वीट किया है। इस बीत पीएम मोदी ने चुनावों के ऐलान के बाद देश की जनता से आशीर्वाद मांगा है और ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की है।

फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आया

विद्युत जामवाल की जंगली २९ मार्च को रिलीज होगी

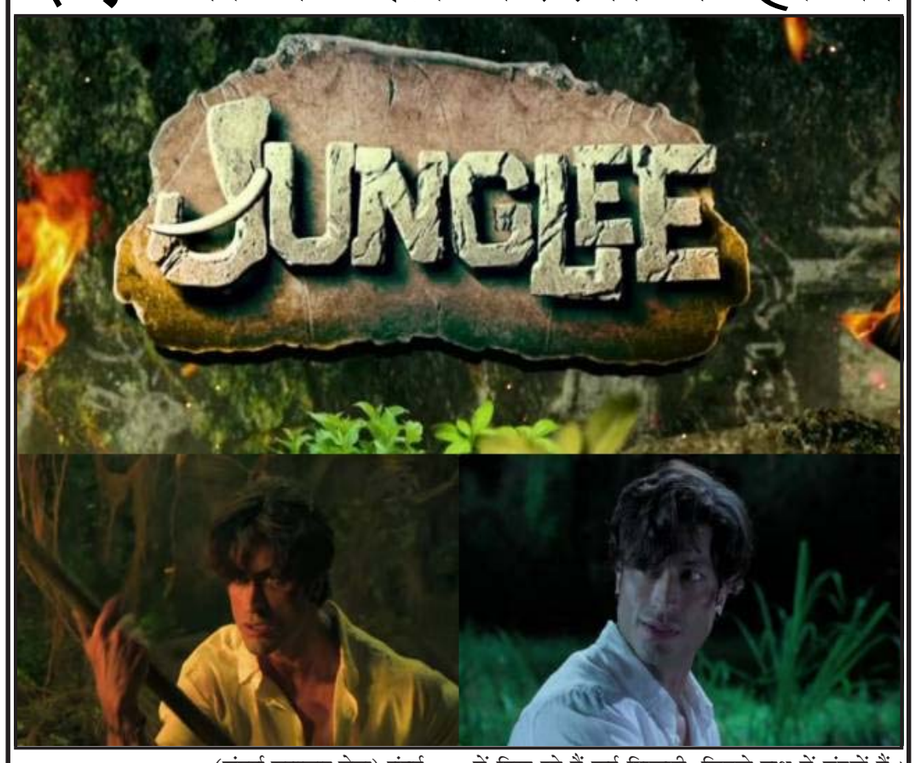

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई,

बॉलिवुड ऐक्टर विद्युत जामवाल की अगली फिल्म जंगली को लेकर इन दिनों काफी चर्चा है। इस फिल्म का ट्रेलर दर्शकों को काफी पसंद आया, जिसे अब तक २ करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। फिल्म रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैन्स के लिए हमारे पास एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनका यह इंतजार बहुत जल्द खत्म होनेवाला है। फिल्म जो पहले ५ अप्रैल को रिलीज होनेवाली थी, अब खबर है कि इसे एक सप्ताह पहले रिलीज किया जा रहा है। इसी के साथ फिल्म का एक नया पोस्टर भी जारी किया गया है। लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें तो फिल्म जंगली की रिलीज डेट ५ अप्रैल से पहले कर दी गई और अब यह फिल्म २९ मार्च को सिनेमाघरों में छा जाएगी। बता दें कि इस फिल्म में एक बार फिर विद्युत का ऐक्शन पैक्ड अवतार देखने को मिलने वाला है यानी विद्युत जामवाल के रूप में बच्चों को इंडियन टार्जन देखने को मिलेगा। मेकर्स ने इस घोषणा के साथ-साथ इस फिल्म का एक नया पोस्टर पर रिलीज. किया है, जिसमें विद्युत जामवाल नमस्कार की मुद्रा में हाथी के सामने खड़े नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर के बैकग्राउंड में दिख रहे हैं कई शिकारी, जिनके हाथ में बंदूकें हैं। बता दें कि फिल्म हाथी (भोला) और इंसान (राज-विद्युत) के बीच की दोस्ती और फिर लालची शिकारियों से जंगल के जानवरों को बचाने की कहानी के बीच उलझी है, जो दर्शकों के इमोशंस को छूने का दम रखती है।फल्म जो पहले ५ अप्रैल को रिलीज होनेवाली थी, अब खबर है कि इसे एक सप्ताह पहले रिलीज किया जा रहा है। इसी के साथ फिल्म का एक नया पोस्टर भी जारी किया गया है। लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें तो फिल्म जंगली की रिलीज डेट ५ अप्रैल से पहले कर दी गई और अब यह फिल्म २९ मार्च को सिनेमाघरों में छा जाएगी। बता दें कि इस फिल्म में एक बार फिर विद्युत का ऐक्शन पैक्ड अवतार देखने को मिलने वाला है यानी विद्युत जामवाल के रूप में बच्चों को इंडियन टार्जन देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, इस फिल्म में प्राचीन मार्शल आर्ट की तकनीक कलारिपयट्टु और एनिमल मूवमेंट का खास मिक्सचर दिखेगा। बड़े पर्दे पर करीब ४० साल बाद असली हाथी देखे जा सकेंगे। फुल ऐक्शन से भरपूर यह फिल्म जंगली जानवरों से इंसान की दोस्ती की मिसाल दिखाने जा रही है।

एक बार फिर विद्युत का ऐक्शन पैक्ड अवतार दिखेगा

पहले चरण में ११ अप्रैल को वोटिंग

लोकसभा चुनाव २०१९ का ऐलान

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली ,

लोकसभा चुनाव २०१९ का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने आज देश के ५४३ लोकसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। विज्ञान भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने फेज वाइज चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। कुल ७ चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण की वोटिंग ११ अप्रैल को होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल ३ जून को खत्म हो रहा है। सात चरण की चुनाव की जानकारी नीचे के अनुसार है।

प्रथम चरण में वोटिंग

पहले चरण में कुल ९१ सीटों पर वोटिंग। कुल २० राज्यों में होगी वोटिंग। - पहले चरण की अधिसूचना जारी होने की तारीख- १८-०३-२०१९। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख-२४-०३-२०१९। - नामांकन पत्रों की जांच-२६ मार्च। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख- २८ मार्च। वोटिंग-११ अप्रैल। काउंटिंग-२३ मई।

आंध्र प्रदेश -२४, अरुणाचल -२, असम-५, बिहार-४, छत्तीसगढ़-१, जम्मू-कश्मीर-२, महाराष्ट्र-७, मणिपुर-१, मेघालय-२, मिजोरम-१, नागालैंड-१, ओडिशा-४, सिक्किम-१, तेलंगाना-१७, त्रिपुरा-१, यूपी-८, उत्तराखंड-५, पश्चिम बंगाल-२, अंडमान ऐंड निकोबार-१, लक्षद्वीप-१, दादरा एवं नगर हवेली-१, कुल-९१ सीट

दूसरे चरण में चुनाव

दूसरे चरण के लिए १३ राज्यों की ९७ लोकसभा सीटों पर १८ अप्रैल को वोटिंग होंगी। इस चरण के लिए १९ मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख २६ मार्च को होगी। २७ मार्च को दूसरे चरण के नामांकनों की जांच होगी। २९ मार्च तक नामांकन वापस किया जा सकेगा। दूसरे चरण में असम की ५, बिहार की ५, छत्तीसगढ़ की ३, जम्मू-कश्मीर की २, कर्नाटक की १४, महाराष्ट्र की १०, मणिपुर की १, ओडिशा की ५, तमिलनाडु की सभी ३९, त्रिपुरा की १, उत्तर प्रदेश की ८, पश्चिम बंगाल की ३ और पुदुचेरी की एक सीट के लिए १८ अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। तीसरे फेज में सबसे ज्यादा सीटों पर होगा चुनाव

तीसरे फेज की बात करें तो १४ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ११५ सीटों को शामिल किया गया है। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव होगा।

सीट : ११५ लोकसभा क्षेत्र, नोटिफिकेशन: २८ मार्च, नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख: ४ अप्रैल, स्कूटनी की तारीख: ५ अप्रैल, नामांकन वापस लेने की तारीख: ८ अप्रैल, वोटिंग की तारीख: २३ अप्रैल, नतीजे: २३ मई

असम : ४, बिहार: ५ छत्तीसगढ़: ७ गुजरात: २६ गोवा: २ जम्मू और कश्मीर: १ कर्नाटक: १४ केरल: २० महाराष्ट्र: १४ उड़ीसा: ६ यूपी: १० पश्चिम बंगाल: ५ दादरा और नगर हवेली: १ दमन दीव: १।

चौथे चरण में कब कहां चुनाव

लोकसभा चुनाव २०१९ की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने बताया कि इसबार मतदान ७ चरणों में होगा। वहीं २३ मई को वोटों की गिनती होगी। चौथे चरण की बात करें तो इसमें ९ राज्यों की ७१ सीटों पर वोटिंग होगी। इसके लिए २९ अप्रैल को वोटिंग होगी। इसमें बिहार (५), जम्मू कश्मीर (१) झारखंड (१), मध्यप्रदेश (६), महाराष्ट्र (१७), उड़ीसा (६), राजस्थान (१३), यूपी (१३), बंगाल (८) और ओडिशा (६) में वोटिंग होगी।

पांचवें चरण में सात राज्यों में मतदान

चुनाव आयोग ने १७वीं लोकसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव सात चरणों में होगा। पहले चरण का मतदान ११ अप्रैल और दूसरे चरण का मतदान १८ अप्रैल को होगा। तीसरा चरण २३ अप्रैल, चौथा चरण २९ अप्रैल, पांचवां ६ मई, छठा १२ मई और सातवां चरण १९ मई को होगा। पांचवें चरण में जिन राज्यों और लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है।

सीट- ५१ लोकसभा सीट, राज्य- ०७ प्रदेश, अधिसूचना जारी होने की तारीख- १६ अप्रैल

वोटिंग- ६ मई, ५वें चरण में किस राज्य में कितनी सीटों पर मतदान।

बिहार- ०५, जम्मू-कश्मीर- ०२, झारखंड- ०४, मध्य प्रदेश- ०७, राजस्थान- १२, उत्तर प्रदेश- १४, पश्चिम बंगाल- ०७, कुल- ५१ सीट (आगे का शेष)

१२ मई को छठे चरण का चुनाव, ५९ सीटों पर वोटिंग

छठवें चरण के चुनाव की बात करें तो ये १२ मई को कराए जाएंगे। छठे फेज में ७ राज्यों की ५९ सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे। सातों चरण के मतदान के बाद २३ मई को मतगणना होगी। आम चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में चुनाव आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। आपको बता दें कि २०१४ में १६वीं लोकसभा का चुनाव ९ चरणों में कराया गया था। छठे चरण का चुनाव- १२ मई, सीटें- ५९, राज्य- ७, फेज ६ में सीटें : बिहार (८), हरियाणा (१०), झारखंड (४), मध्य प्रदेश (८), उत्तर प्रदेश (१४), पश्चिम बंगाल (८), दिल्ली-हृष्टक्र(७)।

सातवें चरण में ५९ सीटों पर ८ राज्यों में वोटिंग

सातवें और अंतिम चरण की वोटिंग १९ मई को होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देशभर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल ३ जून को खत्म हो रहा है। अधिसूचना जारी होने की तारीख -२२ अप्रैल, कुल सीटें -५९, कुल राज्य-८, वोटिंग- १९ मई, मतगणना-२३ मई।

कहां-कहां कितनी सीटों पर वोटिंग : बिहार-८, झारखंड-३, मध्य प्रदेश-८, पंजाब-१३, पश्चिम बंगाल-९, चंडीगढ़-१, यूपी-१३, हिमाचल-४

जम्मू-कश्मीर चुनाव को लेकर सरकार पर निशाना

मायावती, फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना

सभी दल चाहते हैं चुनाव हो तो फिर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकते : फारूक

(संपूर्ण समाचार सेवा) लखनऊ,

लोकसभा चुनाव के साथ जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाने के चुनाव आयोग के फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती और नैशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि यह मोदी सरकार की कश्मीर नीति की विफलता की निशानी है। वहीं, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब सभी दल चाहते हैं कि चुनाव हो तो फिर लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो सकते। फारूक अबदुल्ला ने पत्रकारों से कहा, सभी दल जम्मू-कश्मीर में एक साथ चुनाव के पक्ष में हैं। लोकसभा चुनाव के लिए माहौल अनुकूल है लेकिन जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए क्यों नहीं ? स्थानीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण हुए, यहां पर्याप्त सुरक्षा बल मौजूद है फिर क्यों विधानसभा चुनाव नहीं हो सकते ? मायावती ने ट्वीट कर लिखा, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा का आम चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं कराना मोदी सरकार की कश्मीर नीति की विफलता का निशानी है। जो सुरक्षा बल लोकसभा चुनाव करा सकते हैं, वही उसी दिन वहां विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं करा सकते हैं ? केन्द्र का तर्क बेतुका है और बीजेपी का बहाना बचकाना है। फारूक अब्दुल्ला ने एयर स्ट्राइक को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, हमें हमेशा से पता था कि पाकिस्तान के साथ युद्ध के साथ छोटी लड़ाई हो सकती है। लेकिन एयर स्ट्राइक इसलिए हुई क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। हमने करोड़ों की लागत का एक एयरक्राफ्ट खो दिया। शुक्र है कि पायलट (विंग कमांडर अभिनंदन) बच गया और सम्मान के साथ पाकिस्तान से लौट आया। बता दें कि लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव आयोग ने एक ओर चार राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराने की भी घोषणा की है, हालांकि आयोग ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा भंग होने के बावजूद भी राज्य में चुनाव ना कराने की घोषणा की। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्तसुनील अरोड़ा ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव ना कराने की बात कहते हुए कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से फिलहाल राज्य में विधानसभा चुनाव की वोटिंग नहीं कराई जाएगी।

चुनाव पहले ही कांग्रेस को एक और झटका

कांग्रेस के विधायक वल्लभ धारवीया भाजपा में शामिल

कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वाघाणी सहित के सीनियरों की उपस्थिति में भाजपा में शामिल

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस की राजनीति में और एक बार हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस में एक के बाद एक विधायक पार्टी छोड़ रहे हैं और भाजपा में शामिल हो रहे है, जिसे लेकर कांग्रेस के पार्टी के स्थानीय नेताओं से लेकर हाईकमान तक के नेता चिंतित हो गए हैं। पिछले १५ दिनों में कांग्रेस के चार विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस से इस्तीफा देकर वल्लभ धारवीया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जीतू वाघाणी सहित के सीनियरों की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। धारवीया ने कांग्रेस में प्रदेश स्तर पर काफी खींचतान चल रहे होने सहित के गंभीर आरोप लगाये। भाजपा में शामिल होने के बाद वल्लभभाई ने बताया कि, मुझे सत्ता की लालच नहीं है और आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि, भाजपा की संगठन शक्ति है यह कांग्रेस में देखने को नहीं मिलती है। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है। मैंने अमित शाह और नरेन्द्र मोदी के अंदर में काम किया था। कांग्रेस में जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि पार्टी में कुछ नहीं है। मेरा जन्म ही भाजपा में हुआ यह कहा जाएगा। इसलिए मैं घर वापस आया हूं। जामनगर ग्रामीण के कांग्रेस के विधायक वल्लभ धारवीया ने सोमवार को दोपहर में इस्तीफा देने से जामनगर के स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई। जामनगर सीट पर से हार्दिक पटेल ने लड़ने की तैयारी को लेकर चुनाव के पहले भाजपा ने मास्टर स्ट्रोक लगाकर जिला के सथवारा समाज के मत को अपने कब्जे में ले लिया हो। गुजरात में १९६१ के बाद १२ मार्च को कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होनेवाली बैठक के पहले कांग्रेस को और एक झटका लगने से यह मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई है। जामनगर लोकसभा चुनाव के पहले ही भाजपा द्वारा और एक विधायक शामिल होने की घोषणा को लेकर राजनीति हलचल तेज हो गई।

जनरल कोटा मामले को संविधान पीठ में भेजने पर

इस मामले में २८ मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

१० फीसदी आरक्षण के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम में जनहित याचिका दायर की गई है

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह सामान्य श्रेणी के गरीबों को १० प्रतिशत आरक्षण देने के मामले को अभी संविधान पीठ के समक्ष भेजने का आदेश देने के पक्ष में नहीं है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि वह २८ मार्च को याचिका पर सुनवाई करेगी और संविधान पीठ को मुद्दा भेजने या नहीं भेजने पर विचार करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी शामिल थे। पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील राजीव धवन को अपने आवेदन में उठाये गये बिन्दुओं को एक छोटे नोट में दायर करने को कहा है। आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों को नौकरी और शैक्षिक संस्थानों में १० फीसदी आरक्षण के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य श्रेणी के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में १० प्रतिशत आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन बिल को संसद मंजूरी मिल गई थी। इस बिल को मंजूरी मिलने के अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में एक संगठन ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। यूथ फॉर इक्वैलिटी नाम के संगठन की याचिका में संविधान संशोधन को आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बताया है। जनरल कोटा को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि आर्थिक मापदंड आरक्षण का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। याचिका में इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया गया है। संगठन ने जनरल कोटा को समानता के अधिकार और संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ बताया। याचिका में यह भी कहा गया है कि गरीबों को १० प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान नागराज बनाम भारत सरकार मामले में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भी खिलाफ है।

नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ीं

मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने दायर की नई चार्जशीट

यह चार्जशीट मामले में नए सबूत सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा दायर की गई है

(संपूर्ण समाचार सेवा) मुंबई,

पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुंबई की एक अदालत में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ नई चार्जशीट दायर की गई है। यह चार्जशीट मामले में नए सबूत सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के द्वारा दायर की गई है। १३००० करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले का आरोपी नीरव मोदी फिलहाल लंदन में है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी लंदन के पॉश इलाके के एक बेहद ही महंगे अपार्टमेंट में रह रहा है, साथ ही उसने वहां हीरे का कारोबार भी शुरू कर दिया है। भारतीय एजेंसियों ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए पिछले साल से ही यूके (यूनाइटेड किंगडम) सरकार के पास अर्जी दे रखी है। प्रत्यर्पण की अर्जी मिलने की पुष्टि यूके सरकार ने भी की है। वहां की सरकार ने शनिवार को यह भी बताया था कि भारतीय एजेंसियों की मांग को कोर्ट को रेफर कर दिया गया है। शनिवार को यूके के अखबार द टेलिग्राफ ने नीरव मोदी के लंदन में होने का एक विडियो जारी किया था। इस विडियो में पीएनबी स्कैम का आरोपी बेफिक्र होकर लंदन की सड़कों पर घूमता दिखा था, हालांकि उसने अखबार के रिपोर्टर के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। मोदी का लंदन का यह विडियो सामने आने के बाद सीबीआई ने इंटरपोल और यूके अथॉरिटीज से सम्पर्क साधकर भगोड़े कारोबारी के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर कार्रवाई कर तुरंत गिरफ्तारी की मांग कर चुकी है।

राहुल-सोनिया की मौजूदगी में मंगलवार को कांग्रेस में शामिल होंगे हार्दिक पटेल

अहमदाबाद। पाटीदार आंदोलन के अगुआ हार्दिक पटेल ने 12 मार्च (मंगलवार) को गांधीनगर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल होने का एलान किया है। हार्दिक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी खुद दी है। मंगलवार को ही गांधीनगर में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक प्रस्तावित है। बाद में एक रैली का भी आयोजन किया जाएगा। हार्दिक ने अप्रैल 2015 में पाटीदार आरक्षण आंदोलन समिति के बैनर तले विसनगर में अपना पहला आंदोलन किया था। भाजपा विधायक के कार्यालय पर तोड़फोड़ और आगजनी के बाद हार्दिक चर्चा में आए थे। पिछले साल जुलाई में विसनगर कोर्ट ने इस मामले में उन्हें दो वर्ष की सजा सुनाई थी। इस सजा के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की है जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है। अगर सजा में राहत नहीं मिलती है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक दो वर्ष की सजा मिलने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 (3) के तहत कोई भी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि हार्दिक के कदम से यह साबित हो गया कि वह कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। उनका आंदोलन भी कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा था। हार्दिक ने अपने समुदाय को धोखा देने के साथ ही युवाओं को गुमराह किया है। अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो पाटीदार समुदाय उनको करारा जवाब देगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा ने कहा कि अभी तक हार्दिक सामाजिक आंदोलन चला रहे थे। उनके कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी मजबूत होगी।

पड़ोसी द्वारा बलात्कार का मामला

एक पड़ोसी ने तीन वर्षीय बच्ची का बलात्कार किया

(संपूर्ण समाचार सेवा) अहमदाबाद,

गुजरात के मोरबी नगर में पड़ोसी द्वारा कथित रूप से एक तीन वर्षीय बच्ची के बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घटना शनिवार की है। बच्ची मोरबी कस्बे की इंदिरा नगर कॉलोनी में आरोपी रमेश कोली के घर गई थी। मोरबी बी-मंडल पुलिस थाने के उपनिरीक्षक एबी जडेजा ने कहा, जब बच्ची आरोपी के घर गई तब वह अकेला था। उसने कथित रूप से उसका बलात्कार किया। लौटने के बाद उसके परिजन ने उसके कपड़ों पर खून लगा देखा। इसके बाद वह कोली के घर पहुंचे और वहां भी खून देखा। जडेजा ने कहा कि इसके बाद बच्ची के परिजन ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार के सिलसिले में भारतीय दंड संहिता की धाराओं तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि पीड़िता को अस्पताल ले जाया गया। फरार आरोपी को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

मेरा मंत्र अथक काम करना है : नितिन गडकरी

पीएम पद का उम्मीदवार बनने की मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है

मैंने न तो राजनीति और न ही काम में कोई भी हिसाब-किताब किया, कभी कोई लक्ष्य तय नहीं किया : गडकरी

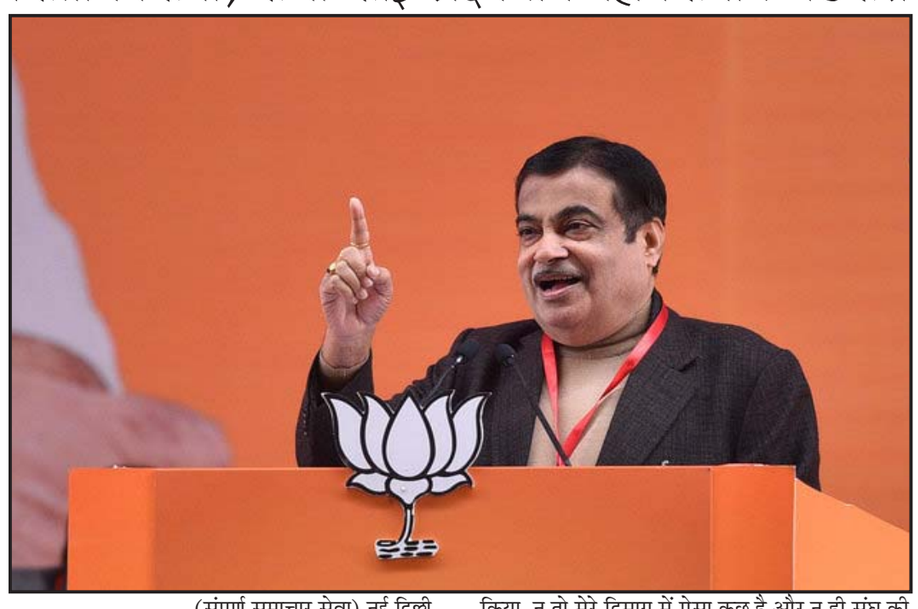

(संपूर्ण समाचार सेवा) नई दिल्ली,

प्रधानमंत्री पद के दावेदारी की तमाम अटकलों के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट कहा कि न ही कोई ऐसी कोई महत्वाकांक्षा है और न ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की उन्हें उम्मीदवार के रूप में पेश करने की मंशा है। आगामी लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत न आने की स्थिति में बीजेपी द्वारा गडकरी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने के कयासों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वह दौड़ में शामिल नहीं हैं। नितिन गडकरी जोर देकर कहा कि उनका मंत्र अथक काम करना है। गडकरी ने कहा, मैंने न तो राजनीति और न ही काम में कोई हिसाब-किताब किया, कभी कोई लक्ष्य तय नहीं किया। मैं तो चला, जिधर चले रास्ता। जो काम दिखा, करता गया। मैं अपने देश के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने में भरोसा करता हूं। बीजेपी की ओर से उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने संबंधी अटकलों को खारिज करते हुए गडकरी ने स्पष्ट किया, न तो मेरे दिमाग में ऐसा कुछ है और न ही संघ की ऐसी कोई मंशा है। हमारे लिए देश सबसे ऊ पर है। उन्होंने कहा, मैं सपने नहीं देखता, न तो मैं किसी के पास जाता हूं और न ही लॉबिंग करता हूं। मैं इस दौड़ में नहीं हूं। मैं अपने दिल से आपको यह बात बता रहा हूं। पूर्व बीजेपी प्रमुख नितिन गडकरी ने इन अटकलों के बारे में आगे कहा कि वह यह नहीं जानते कि लोग क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनका इससे दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। गडकरी ने कहा, मैं और पार्टी मोदीजी के पीछे मजबूती से खड़ी है और वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने विपक्षी दलों के महागठबंधन को महामिलावट करार देते हुए कहा, हमने जो काम किया है, उसे देखकर लगता है कि मोदीजी के नेतृत्व में हमें पिछली बार से अधिक सीटें मिलेंगी। गडकरी ने कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनने की होड़ में होने संबंधी अटकलों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिया था।

चुनाव की तारीखों पर न करें राजनीति

क्या रोजा रहकर मुस्लिम काम नहीं करते: ओवैसी

(संपूर्ण समाचार सेवा) हैदराबाद,

रमजान में लोकसभा चुनाव की तारीखें पड़ने पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जहां कुछ मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं ने रमजान के महीने में वोटिंग कराने पर सवाल उठाया है, वहीं ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस मसले पर राजनीति न की जाए। उन्होंने कहा कि रमजान के महीने में चुनाव होना अच्छा है और मुसलमान इस महीने में ज्यादा वोट करेगा। ओवैसी ने कहा कि वह रमजान में चुनाव का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि वह रमजान में रोजा भी रहेंगे और वोट डालने भी जाएंगे। ओवैसी ने कहा, रमजान से वोटिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पर राजनीति न की जाए। यह गैर जरूरी विवाद पैदा किया जा रहा है। आपको रमजान के बारे में क्या मालूम है ? उन्होंने कहा, चांद दिखने के बाद रमजान पांच मई से शुरू होगा। ईद चार या पांच जून में पड़ेगी। चुनाव आयोग को चुनावी प्रॉसेस तीन-चार जून से पहले खत्म कर लेना है। ओवैसी ने कहा कि वह रमजान में चुनाव का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि वह रमजान में रोजा भी रहेंगे और वोट डालने भी जाएंगे। ओवैसी ने कहा, रमजान से वोटिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस पर राजनीति न की जाए। यह गैर जरूरी विवाद पैदा किया जा रहा है। जाहिर है कि रमजान से पहले चुनावी प्रॉसेस खत्म नहीं किया जा सकता और ईद के बाद चुनाव हो नहीं सकते। यह बात हर किसी को समझने की जरूरत है। बिना वजह इस पर राजनीति न की जाए।

चुनाव में १००% मतदान के लिए

घर-घर जाकर अभियान चलाएंगे RSS कार्यकर्ता

(संपूर्ण समाचार सेवा) भोपाल,

एक ओर निर्वाचन आयोग रविवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर रहा था, वहीं दूसरी ओर ग्वालियर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में भी इसकी गूंज सुनाई दी। संघ ने कहा है कि वह १०० प्रतिशत मतदान कराने के लिए अभियान चलाएगा और यह दावा भी किया गया कि राम मंदिर बनकर रहेगा, उसी जमीन पर जिस पर उसके निर्माण का फैसला किया जा चुका है। चुनावों में संघ की भूमिका के बारे में आरएसएस सरकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा, आरएसएस की भूमिका साफ है। हम १०० प्रतिशत वोटिंग के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। हमारा समाज वक्त के साथ और भी ज्यादा सफाई से सोचने लगा है और आम लोगों को पता है कि कौन देश की बेहतरी के लिए काम करता है।

RNI No. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 and Published from TF-01, Nanakram Super Market,Ramnager,Sabarmati, Ahmedabad - 380 005.Editor : MANOJKUMAR CHAMPKLAL SHAH